



## The Uttar Pradesh Bhikshavriti Pratishedh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978

Act 21 of 1978

**Keyword(s):**

**Beggar, Court, Juvenile Justice Board, Probation Officer, Public Place**

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिबंध (संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1978)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 23 अगस्त, 1978 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 29 अगस्त, 1978 ई० की बैठक में स्वीकृत किया)

[‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 4 सितम्बर, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय प्रसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खंड (क) में दिनांक 6 सितम्बर, 1978 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिबंध अधिनियम, 1975 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिबंध (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

2—उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिबंध अधिनियम, 1975 की धारा 10 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

“(5) यदि पूर्ववर्ती अंतिम उपधारा के अधीन किसी व्यक्ति को भिक्षुक माना जाय तो न्यायालय निम्नलिखित कोई आदेश दे सकता है, अर्थात्:—

(क) यदि मामले की परिस्थितियों से न्यायालय का समाधान हो जाय कि उस व्यक्ति द्वारा, जो पूर्वोक्त रूप से भिक्षुक माना गया है, पुनः भिक्षा मांगने की सम्भावना नहीं है तो वह उस व्यक्ति को, सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् प्रतिभू सहित या रहित इस बन्ध-पत्र पर छोड़ सकता है कि वह उस अवधि में, जिसमें बन्ध-पत्र प्रवृत्त रहे, भिक्षा मांगने से प्रविरत रहेगा और सदाचार रखेगा;

(ख) न्यायालय उसे किसी प्रमाणित संस्था में ऐसी अवधि के लिए जो एक वर्ष से कम न होगी और दो वर्ष तक विस्तृत हो सकेगी, निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय किसी अनुवर्ती आदेश द्वारा, और अनिलिखित किये जाने वाले कारणों से, ऐसी निरोध अवधि को कम कर सकता है।”

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 23 मार्च, 1978 ई० का सरकारी प्रसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3-खंड (क) देखिये।]

PRICE 15 PAISE

विधान सभा  
(राज्यपाल प्रकाशन)

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 36,  
1975 की धारा  
10 का संशोधन

L.A.  
15/78-21  
exp.